देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए स्कैन करें और महानगर टाइम्स को लाइक व सब्सक्राइब करें।
facebook Instagram twitter YouTube

एमएसएमई: ऑटो कंपोनेंट कंपनियों के पास 98 हजार करोड़ का स्टॉक फंसा

महानगर टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली । भारतीय ऑटो कंपोनेंट उद्योग में करीब 98,000 करोड़ रुपए का स्टॉक फंसा हुआ है, इसमें से 29 हजार से 39 हजार करोड़ रुपए तक की राशि स्टॉक प्रबंधन में सुधार करके जारी की जा सकती है। यह राशि कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग हो सकती है। एमएसएमई क्षेत्र को इससे 4,000 से 5,600 करोड़ रुपए का लाभ मिल सकता है। वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट बताती है कि देश के 80 फीसदी ऑटो कंपोनेंट निर्माता एमएसएमई हैं। खपत-आधारित इस्तेमाल का तरीका अपनाने वाली कंपनियां 30 से 40 फीसदी तक स्टॉक कम कर सकती हैं। भारत के ऑटो कंपोनेंट एमएसएमई का कुल राजस्व लगभग 2.4 से 2.9 लाख करोड़ रुपए है। उत्पादकता में 30 फीसदी सुधार से 74 हजार से 88 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक राजस्व मिल सकता है। सामग्री लागत के बाद यह 29 हजार से 44 हजार करोड़ रुपए का वृद्धिशील मूल्य पूल बना सकता

है। इन लाभों से एक आत्म-सुदृढ़ निवेश चक्र बन सकता है। परिचालन सुधारों से कार्यशील पूंजी मुक्त होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। इससे बाहरी पूंजी तक पहुंच भी बेहतर होगी।

एमएसएमई भविष्य के लिए तैयार नहीं: वेक्टर के अध्ययन से पता चला कि 95 फीसदी उद्योग नेता मानते हैं कि एमएसएमई भविष्य की वृद्धि के लिए पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे। यह अध्ययन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) के 66वें वार्षिक सत्र में जारी किया गया था। शोध में भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक क्षमताओं और वर्तमान में उपलब्ध क्षमताओं के बीच बड़ा अंतर पाया गया। यह अंतर ऑटोमोटिव एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं और टियर-1, टियर-2 कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के इनपुट पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए जुलाई से अगस्त 2026 तक 21 वरिष्ठ उद्योग अधिकारियों से डेटा एकत्र किया गया था।

विनिर्माण क्षमता को बरकरार रखना चुनौती: अध्ययन में क्षमता का विरोधाभास भी सामने आया है। संयंत्र औसतन 75 से 85 फीसदी क्षमता उपयोग पर चल रहे हैं। फिर भी, 91 फीसदी उत्तरदाताओं ने क्षमता को एक बड़ी चुनौती माना। बार-बार होने वाले बदलाव, गुणवत्ता में हानि और पुनः कार्य और खराब सामग्री प्रवाह प्रभावी उत्पादक क्षमता को कम करते हैं। वेक्टर कंसल्टिंग ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर रविंद्र पटकी ने कहा कि अवसर केवल अधिक क्षमता जोड़ने का नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों के पास जो क्षमता है, उसका एक बड़ा हिस्सा उत्पादक उत्पादन में नहीं बदल रहा है।

भारत के लिए आगे है महत्वपूर्ण

रविंद्र पटकी के अनुसार परिचालन में फंसी नकदी को मुक्त करना महत्वपूर्ण है। मौजूदा कारोबार की अर्थव्यवस्था में सुधार करना और अधिशेष को क्षमताओं में लगाना जरूरी है। यह तय करेगा कि भारतीय आपूर्तिकर्ता भविष्य की ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में कैसे बढ़ेंगे। रिपोर्ट कहती है कि भारत के ऑटोमोटिव आपूर्तिकर्ता आधार को मजबूत करना उद्योग की प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण है। वाहन का मूल्य बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। भारत की घरेलू स्थानीयकरण और वैश्विक सोर्सिंग की अगली लहर पर कब्जा करने की क्षमता आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करेगी।

व्यापार और कॉरपोरेट जगत

बायजू से जुड़ी के-3 एजुकेशन की संपत्तियों की नीलामी पर रोक

महानगर टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज में डूबी एजुटेक कंपनी बायजू से जुड़ी के-3 एजुकेशन की संपत्तियों की नीलामी पर रोक लगा दी है। के-3 एजुकेशन बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (टीएलपीएल) की सहायक कंपनी है। कंपनी पर लगभग 150 करोड़ रुपए मूल्य की अपनी संपत्तियों को मात्र 16 करोड़ रुपए में बेचने के आरोप थे।

यह आदेश के-3 एजुकेशन के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) और क्रिटिकल सॉल्यूशंस की ओर से दायर उस याचिका पर आया है, जिसमें स्वामित्व के सत्यापन तक संपत्तियों की सुरक्षा की मांग की गई थी। न्यायाधिकरण ने कंपनी को संपत्तियों के निपटान पर आगामी 21 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। टाटा टेक्नोलॉजी के पूर्व सीईओ ने बेचे 165 करोड़ के शेयर: टाटा टेक्नोलॉजीज के पूर्व सीईओ एवं

प्रबंध निदेशक पैट्रिक रेमन मैकगोल्ड्रिक ने बीएसई पर खुले सौदे के जरिए लगभग 165 करोड़ रुपए के शेयर बेचकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। मैकगोल्ड्रिक ने चार चरणों में 21 लाख शेयर बेचे। ये शेयर पुणे स्थित वैश्विक उत्पाद इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवा कंपनी में 0.51 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर हैं। शेयर 785 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर बेचे गए, जिससे लेनदेन का कुल मूल्य 164.85 करोड़ रुपए रहा। शेयर बिक्री के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज में मैकगोल्ड्रिक की हिस्सेदारी 1.13 प्रतिशत से घटकर 0.62 फीसदी रह गई।

सरकार के प्याज बेचने के बाद भी बढ़ रही कीमतें देश में औसत भाव 50.79 रुपए प्रति किलो पहुंचा

महानगर टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बफर स्टॉक से सस्ती दर पर प्याज बेचने के बावजूद कीमतें नहीं घटी है। सरकार 17 शहरों में 35 रुपए प्रति किलो के भाव पर प्याज बेच रही है। इसके बावजूद पूरे देश में प्याज का औसत खुदरा भाव 48.5 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 50.79 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के पहले 10 दिनों में लगभग 4 हजार टन बफर प्याज की बिक्री की जा चुकी है। इसके बावजूद महानगरों में प्याज के दाम ऊंचे बने हुए हैं।

दिल्ली में 65 और चेन्नई में 63 प्रति किलो बिका: देश के प्रमुख शहरों में प्याज की कीमतों में बड़ा अंतर देखा गया। दिल्ली में प्याज 65 प्रति किलो, मुंबई में 53 प्रति किलो, चेन्नई में 63 प्रति किलो और रांची में 40 प्रति किलो के भाव पर बिका। वहीं, देश भर में प्याज का औसत थोक भाव 42.79 प्रति किलो दर्ज किया गया।

अफसरों का दावा- बफर सेल से कीमतों में 2 से 3 रुपए की आई कमी

निधि खरे के मुताबिक बफर स्टॉक जारी होने से स्थानीय स्तर पर कीमतों में हल्की नरमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकारी बफर का प्याज साइज और क्वालिटी में निजी व्यापारियों के प्याज के बराबर ही है। वहीं, एनसीसीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिस जोसेफ चंद्रा ने कहा कि उनकी एजेंसी ने अब तक अलग-अलग शहरों में 1,500 टन बफर प्याज बेच दिया है। उनका फोकस रिटेल स्तर पर 35 प्रति किलो के भाव पर सीधे उपभोक्ताओं तक प्याज पहुंचाने पर है।

कांदा एक्सप्रेस ट्रेन और ट्रकों से पहुंचाई जा रही खेप: सरकार साल 2026 के लिए बनाए गए अपने 1.21 लाख टन के बफर स्टॉक में से प्याज जारी कर रही है। यह काम नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन और नैफेड के जरिए हो रहा है। उत्पादक राज्यों से प्याज को ट्रकों और रेलवे की विशेष मालगाड़ी 'कांदा एक्सप्रेस' के जरिए उन शहरों में भेजा जा रहा है जहां कीमतें ज्यादा बढ़ रही हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि दिल्ली और चेन्नई के लिए भारी मात्रा में प्याज भेजा जा चुका है।

मोबाइल वैन और सोसायटी के जरिए रिटेल बिक्री

सस्ते प्याज की बिक्री दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, पंजाब और ओडिशा समेत कई राज्यों में चल रही है। कई राज्य सरकारों ने भी इस योजना में शामिल होने की इच्छा जताई है। एनसीसीएफ राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्याज बांट रहा है। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन प्याज की छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा संभाल रहा है।

कीमतें बढ़ने की यह है मुख्य वजह और आगामी खरीफ सीजन में मिलेगी राहत

निधि खरे ने बताया कि इस साल रबी सीजन की प्याज फसल को कटाई के दौरान बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचा था। रबी की प्याज को ही पूरे साल के लिए स्टोर करके रखा जाता है। हालांकि, सरकार को अब खरीफ सीजन की नई फसल से उम्मीद है। अक्टूबर के मध्य से नई फसल मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी, जिससे सप्लाई बढ़ेगी और बढ़ती कीमतों से स्थायी राहत मिलेगी।

नॉलेज बॉक्स: कांदा एक्सप्रेस और यह है बफर स्टॉक

कांदा एक्सप्रेस: भारतीय रेलवे की स्पेशल पार्सल/फ्रेट ट्रेन, जिसे प्याज उत्पादक इलाकों (जैसे महाराष्ट्र के नासिक) से सीधे बड़े खपत वाले शहरों तक तेज सप्लाई के लिए चलाया जाता है।

बफर स्टॉक का गणित: सरकार 1.21 लाख टन प्याज रिजर्व रखती है, ताकि जब ऑफ-सीजन में दाम अचानक बढ़ें तो इसे बाजार में उतारकर कीमतों को काबू में रखा जा सके।

रूस समेत 21 देश तेल उत्पादन नीति पर लेंगे फैसला, भारत की टिकी निगाहें, पड़ेगा असर

महानगर टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। रूस समेत ओपेक से अधिक समूह के 21 देश एक अहम फैसला लेने वाले हैं। इस पर भारत समेत दुनियाभर की नजरें टिकी हैं। यह ऑयल प्रोडक्शन पॉलिसी से जुड़ा है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रविवार को होने वाली इस बैठक में ओपेक समूह अक्टूबर के लिए अपनी तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने वाला है। इस ग्रुप को उत्पादन के अगले कदमों पर फैसला लेने से पहले नए कोटा पर सहमति बनानी होगी। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से तेल निर्यात में बाधा आ रही है। इससे कीमतों और बाजार हिस्सेदारी पर ओपीईसी का

असर सीमित हो गया है। पहले के मुकाबले अब बाजार पर ग्रुप के सप्लाई से जुड़े फैसलों का असर कम हुआ है।

अपने टारगेट से पीछे है ग्रुप: अगस्त में ओपेक समूह ने सितंबर के लिए उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इससे 2023 में तय की गई 16.5 लाख बैरल प्रति दिन की सप्लाई कटौती को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। उत्पादन बढ़ाने पर सहमति के बावजूद पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और रूस समेत उसके सहयोगियों से बने इस ग्रुप का उत्पादन युद्ध के कारण अभी भी अपने लक्ष्यों से काफी कम है।

ग्रुप का यह है प्लान: ओपेक समूह ने अभी भी उत्पादन में कटौती का एक और दौर लागू कर रखा है। यह 21 देशों के इस ग्रुप के ज्यादातर सदस्यों पर 2026 के आखिर तक लागू रहेगा। कटौती को कैसे खत्म किया जाए और उत्पादन को बाजार में कैसे वापस लाया जाए, इस पर फैसला लेने से पहले ग्रुप को सदस्यों की तेल उत्पादन क्षमता की समीक्षा करनी होगी। मकसद यह है कि 2027 के लिए उत्पादन बेसलाइन तय की जा सके, जो कोटा का आधार बनती है।

शैले होटल्स 2029-30 तक जोड़ेगी 5500 कमरे, हाइब्रिड मॉडल पर जोर

महानगर टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली आतिथ्य क्षेत्र की प्रमुख कंपनी शैले होटल्स लिमिटेड का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक अपने कमरों की संख्या बढ़ाकर लगभग 5,500 करने का है। शैले होटल्स के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) श्वेतांक सिंह ने बताया कि कंपनी अपने पारंपरिक परिसंपत्ति-स्वामित्व मॉडल से आगे बढ़कर यह विस्तार कर रही है। यह विस्तार शैले के व्यावसायिक मॉडल में आए बदलाव को दर्शाता है।

कंपनी अब तीसरे पक्ष द्वारा संचालित होटल, फ्रैंचाइजी संपत्तियों और अपने खुद के 'अथिवा' ब्रांड के तहत होटल को जोड़कर इस लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। कंपनी की आगामी परियोजनाओं के तहत 1,200 से 1,300 कमरे अथिवा ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं। सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' के साथ साक्षात्कार में कहा

कि अब हम केवल परिसंपत्ति-स्वामित्व मॉडल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तीनों मॉडल पर एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास रिट्ज-कार्लटन जैसी संपत्तियां आगे भी रहेंगी, जो तीसरे पक्ष द्वारा संचालित हैं, ताज जैसी फ्रेंचाइजी संपत्तियां होंगी और हमारे अपने ब्रांड अथिवा के तहत भी संपत्तियां रहेंगी। कंपनी के आगामी पोर्टफोलियो में दिल्ली हवाई अड्डे पर 380 कमरों वाला ताज होटल शामिल है। इसके लगभग 70 कमरे चालू वित्त वर्ष के अंत तक खुलने की उम्मीद है। रिट्ज-कार्लटन हैदराबाद, हयात रीजेंसी ऐरोली और उदयपुर होटल के वित्त वर्ष 2028-29 में शुरू होने की संभावना है।

हाल में घोषित पुणे येरवडा परियोजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी के पास इस समय लगभग 3,389 कमरे परिचालन में हैं।

आमसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सेफपैनल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लॉट नंबर एसपी-172, रीको औद्योगिक क्षेत्र, एक्सटेंशन भिवाड़ी, कहारानी, तहसील तिजारा, जिला खैरथल तिजारा, राजस्थान में प्रस्तावित डेकोरेटिव लेमिनेटेड शीट विनिर्माण संयंत्र की क्षमता 55.00 लाख शीट/वर्ष तथा सीपीएफ/एमएफ-रेजिन उत्पादन 13,591 मीट्रिक टन/वर्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है। उक्त परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति (Environmental Clearance) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा पत्र दिनांक 31.08.2026 के माध्यम से प्रदान की गई है। यह परियोजना EIA अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत अनुमोदित है तथा इसकी स्वीकृति संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। परियोजना से संबंधित पर्यावरण स्वीकृति पत्र की प्रति मंत्रालय की वेबसाइट https://parivesh.nic.in पर उपलब्ध है एवं इच्छुक व्यक्ति इसे अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते हैं।

वास्ते
मेसर्स सेफपैनल्स प्राइवेट लिमिटेड
एसपी-172, रीको औद्योगिक क्षेत्र, एक्सटेंशन भिवाड़ी, कहारानी, तहसील तिजारा,जिला, खैरथल-तिजारा, राजस्थान

---

pnb पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक | **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

एआरएमबीः पश्चिम दिल्ली, दूसरी मंजिल, विक्रांत टावर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008
ईमेल– cs8334@pnb.bank.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	क) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / ख) दिनांक के अनुसार बकाया राशि / ग) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	अचल बंधक सम्पत्तियों का विवरण / स्वामित्व का नाम (बंधक सम्पत्तियाँ)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण
1.	एआरएमबी पश्चिमी दिल्ली **मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड** (अपने निदेशक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों नामतः सुहैल सिंह, नम्रता भाटिया, परविंदर सिंह भाटिया के माध्यम से) 2747/6, दूसरी मंजिल, चूना मंडी, पहाड़गंज, मध्य दिल्ली, दिल्ली – 110055 **इसके अलावा:** एफ–27(ए), रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान– 301019 **इसके अलावा:** जी1–127, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान– 301019 **श्री सुहैल सिंह (निदेशक/गारंटायर, मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड)** मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034 **श्रीमती नम्रता भाटिया (निदेशक/गारंटायर, मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड)** मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034 **मैसर्स नीरा मेटल कंपनी अपनी प्रोपराइटर नामतः श्रीमती नम्रता भाटिया के माध्यम से (गारंटायर/बंधककर्ता, मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड)** मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034 **इसके अलावा:** जी1–127, रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान– 301019 **मैसर्स भाटिया ट्रेडिंग कंपनी अपने प्रोपराइटर नामतः श्री परविंदर सिंह भाटिया के माध्यम से (गारंटायर/बंधककर्ता, मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड)** मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034 **इसके अलावा:** एफ–27(ए), रीको औद्योगिक क्षेत्र, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान– 301019 **श्री परविंदर सिंह भाटिया (निदेशक/गारंटायर, मैसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड)** मकान नंबर 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034	क) **01.02.2025** ख) **रु. 21,06,47,133.49/-** साथ ही आगे का ब्याज और शुल्क ग) **30.05.2025** घ) सांकेतिक	**1.** सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत के , निर्मित स्वतंत्र स्वामित्व वाली संपत्ति संख्या 99, जिसका क्षेत्रफल 155.94 वर्ग मीटर (186.53 वर्ग गज) है, जो पब्लिक सेक्टर (P&T) कर्मचारी सेंट्रल को–ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की लेआउट योजना में स्थित है, जिसे संदेश विहार, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 के नाम से जाना जाता है, जिसमें साझा मार्ग एवं सीढ़ियां तथा नीचे स्थित भूमि में 33% अविभाजित हिस्सा भी शामिल है। उक्त संपत्ति श्री परविंदर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह के नाम पर पार्टिशन डीड संख्या 11588 दिनांक 01.08.2019 के माध्यम से है। **चौहद्दी : पूर्व : संपत्ति संख्या 100, पश्चिम: भूमि संपत्ति संख्या 98, उत्तर: 30 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण: सर्विस लेन**	रू. **3.24** करोड़ रू. **32,40,000/-** रू. **2.00** लाख	**24.09.2026** पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	उधारकर्ता ने डीआरटी–2, दिल्ली में एसए नंबर 109/2026 दायर किया था।
		क) **01.02.2025** ख) **रु. 21,06,47,133.49/-** साथ ही आगे का ब्याज और शुल्क ग) **30.05.2025** घ) सांकेतिक	**2.** औद्योगिक भूखंड संख्या G1–127, रीको औद्योगिक क्षेत्र ।। – डी, खुशखेड़ा, अलवर, राजस्थान में, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर, जो बिक्री विलेख संख्या 202103111105213 दिनांक 25.10.2021 के तहत मैसर्स नीरा मेटल कंपनी (प्रोप्राइटर श्रीमती नम्रता भाटिया) के नाम पर दर्ज है। **चौहद्दी:– पूर्व : G1 – 126B, पश्चिम: G1 – 127, उत्तर: 24 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण: G1 – 140, 141**	रू. **3.08** करोड़ रू. **30,80,000/-** रू. **2.00** लाख		
		क) **01.02.2025** ख) **रु. 21,06,47,133.49/-** साथ ही आगे का ब्याज और शुल्क ग) **30.05.2025** घ) सांकेतिक	**3.** इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर एफ–27(ए), रीको इंडस्ट्रियल एरिया खुशखेड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित, जिसका कुल क्षेत्रफल 1877 वर्ग मीटर है, जो कि मैसर्स भाटिया ट्रेडिंग कंपनी (प्रोपराइटर श्री परविंदर सिंह भाटिया के माध्यम से) के नाम पर दस्तावेज संख्या 201803111101647, बुक नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 526, पेज नंबर 47, दिनांक 12.04.2018 के तहत पंजीकृत है। **चौहद्दी: पूर्व : 18 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम: SP30A, उत्तर: F27, दक्षिण: F28**	रू. **4.8862** करोड़ रू. **48,86,200/-** रू. **2.00** लाख		

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. नीलामी बिक्री "ई–नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी। (2) ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (**https://baanknet.com**) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, VIOS कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडी ईस्ट मुंबई–400037 (हेल्पडेस्क नं. 91 8291220220, ईमेल आईडी: **support.baanknet@baanknet.com**) द्वारा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। (3) बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों से युक्त बिक्री नोटिस निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल **(1) https://baanknet.com (2) www.pnbindia.in** पर उपलब्ध/प्रकाशित है। (4) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% जमा करने/बोली राशि की पूर्ण जमा करने के समय ही टीडीएस का भुगतान किया जाना है। (5) संपत्तियों को ''जहां है जैसी है'' और ''जो है जैसी है'' तथा ''जो भी है जैसी है'' के आधार पर बेचा जा रहा है। (6) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (7) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के तहत नोटिस, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ सभी मामलों में जारी किया गया है, (8) बिक्री की विस्तृत शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com , www.pnb.bank.in** देखें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

प्रकाशन की तिथि : 07.09.2026 | स्थानः दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक